Panipat Oil Refinery

*359. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether Government have taken a decision to expand the capacity of the IOC's Panipat Refinery;

(b) if so, the existing refining capacity of the said refinery and what would be its capacity after expansion;

(c) the allocations made for enhancing the refining capacity; and

(d) by when the task of expanding the capacity of the refinery is likely to be completed?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPT. SATISH SHARMA): (a) to (d) Presently, approve capacity of the refinery is 6 MMTPA. IOC has submitted a proposal for further expansion of the Capacity of the refinery by 3.0 MMTPA. The proposal is under process for Ist Stage approval.

The details of the cost estimates allocation and completion schedule etc., would be known only on the completion of the detailed feasibility report.

केन्द्रीय सड़क निधि

*360. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सड़क निधि से संबंधित प्रस्ताव के कार्यान्वयन हेतु गठित की गई मंत्रिमंडल की उप-समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार केन्द्रीय सड़क निधि का राज्य-वार आबंटन कब तक किया जाएगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० राजशेखर मूर्ति): (क) से (ग) संभवतः, माननीय सदस्य केन्द्रीय सड़क निधि में वृद्धि पर मंत्रियों के दल के निर्णय के बारे में जानना चाहते हैं। इस बारे में अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। अभी से यह बताना कठिन है कि संशोधित संकल्प के अनुसार राज्यों को निधियां कब आबंटित की जाएंगी।

Donation Received by Public and Private Institutions

2354. SHRI MOHAMMED AFZAL *alias* MEEN AFZAL: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) what is the amount of assistance and donation received by the public and private institutions during the period 1992-93 and 1993-94 from foreign countries;

(b) what are the names of the institutions and persons who have received such assistance and donations alongwith the amount thereof; and

(c) the amount and the names of countries from which such assistance and donation has been received?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (PROF. M. KAMSON): (a) to (c) Detailed information has been furnished to the Parliament Library in the form of Annual Reports 1992-93 and 1993-94 pertaining to 'Receipt of Foreign Contribution by Voluntary Associations'.

राज्य सरकारों द्वारा बाम्बे हाई से गैस की मांग

*2355. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 जून, 1995 की स्थिति के अनुसार उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने बाम्बे हाई से गैस की मांग की है;

(ख) प्रत्येक जिले में आपूर्ति की उक्त तारीख पर स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा गैस की कितनी मात्रा की मांग की गयी है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपयुक्त निर्णय लिया गया है; और

(घ) महाराष्ट्र से बाहर की उन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें बाम्बे हाई में उपलब्ध अतिरिक्त गैस की आपूर्ति करने के लिए उपयुक्त समझा गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा): (क) महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, हरियाणा पंजाब और दक्षिणी राज्यों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र ने 30 एम एम एस सी एम डी अतिरिक्त गैस की आवश्यकता की सूचना दी है, बिहार ने 6 एम एम एस सी एम डी मांग दर्शाई है और राजस्थान ने 20 एम एम एस सी एम डी गैस की मांग की सूचना दी है। अन्य राज्यों ने निश्चित यात्रा नहीं बताई। पश्चिमी अपतटीय क्षेत्रों से उपलब्ध होने वाली अनुमानित गैस का पूर्णतः आबंटन किया जा चुका है तथा अतिरिक्त आबंटन के अनुरोधों पर विचार नहीं किया जा सकता।

(घ) पश्चिमी अपतटीय क्षेत्रों से गैस का आबंटन निम्नलिखित विद्युत परियोजनाओं को किया जा चुका है:

(एम एम एस सी एम डी)

राज्य / उपभोक्ता	आबंटन
महाराष्ट्र	
एम एस ई बी (उरन)	4.50
टी ई सी (ट्रांबे)	1.50
गुजरात	
एन टी पी सी (कावास)	2.19
राजस्थान	
एन टी पी सी (अन्ता)	1.71
एन टी पी सी (अन्ता अतिरिक्त)	0.24
उत्तर प्रदेश	
एन टी पी सी (औरैया)	2.19
एन टी पी सी (दादरी)	2.93
दिल्ली	
डेसू (इन्द्र प्रस्थ)	0.59
डेसू (बवाना)	1.95
हरियाणा	
एन टी पी सी (फरीदाबाद)	1.95

Introduction of will Technology

2356. SHRI JIBON ROY: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 2180 given in the Rajya Sabha on 23rd August, 1995 and state:

(a) the present status of the WILL trial project;

(b) whether the figure of cost per line of $ 1,760/- is all inclusive as installed or commissioned or merely the FOB import price, if so, what is the total installed and commissioned cost per line;

(c) by when it will be possible to induct the technology in the DOT network;

(d) what is the project cost per line on bulk induction and what will be the counter vailing savings;

(e) whether the technology requires power supply at the subscriber premises; and

(f) the steps proposed to ensure continuity of service in the event of power supply interruption?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATION (SHRI SUKH RAM): (a) Supply of equipment will commence from January, 1966 and systems are expected to be offered for evaluation during March, 1996.

(b) $ 1760 is the total installed and commissioned cost per line.

(c) Telecom Commission has planned induction of technology in DOT network during 1996-97.

(d) There is wide disparity in projected cost per line of WILL equipment by different suppliers / technology. However, it is expected to be much lower than $ 1760 at the time of bulk induction through global tenders.

(e) Yes, Sir, the technology requires power supply at the subscriber premises.

(f) In the event of interruption to public power supply, provision of back up